



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 146]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 1985/श्रावण 3, 1907

No. 146]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 1985/SRAVANA 3, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली

नई दिल्ली 24 जुलाई 1985

विषय—दिल्ली कनाथ मिल का बन्द करने और इसके कामचलाय का  
पुनर्विभाज्य करने के लिए पदनाल करने के लिए एक समिति का  
गठन।

सं एच-11016/31/85 डी. II (ए) —प्रकार न निम्न  
लिखित सदस्यों की एक सरकारी समिति गठित करने का निर्णय लिया है —

1. सदस्य

1. श्री आर. एल. परदीप  
सचिव, सचिव,  
निर्माण और आवास मंत्रालय  
नई दिल्ली।

आयोजक

2. श्री वीरेन्द्र प्रकाश  
मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन  
दिल्ली।

सदस्य

3. श्री अशोक गुप्ता,  
सचिव, सचिव, श्रम मंत्रालय  
नई दिल्ली।

सदस्य

1. श्रम विभाग नई दिल्ली  
का प्रतिनिधि

सदस्य

2. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार है —

(क) उन परिस्थितियों की जांच करना जिनके कारण दिल्ली विकास  
प्राधिकरण के दिनांक 1 फरवरी 1981 के संकल्प संख्या 26  
के अन्तर्गत दिल्ली कनाथ मिल के काम चलाय का पुनर्विभाज्य करने की  
अनुमति दी गई थी।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा उनके दिनांक 14.11.81 के आदेश  
संख्या एफ. 36/10/177702 बी/ए एल सी और व  
अन्तर्गत नगर भूमि अधिग्रहण समा अधिनियम 1976 का  
धारा 27 के साथ पठित धारा 10 (1) के तहत छूट देने की  
परिस्थितियों की जांच करना।

(ग) दिल्ली कनाथ मिल का बन्द करने में सहायक परिस्थितियों  
और नोटिस पर की गई कार्यवाही का कि उन्होंने दिनांक  
27-3-85 के अपने पत्र संख्या 1534 द्वारा श्रमायुक्त तथा  
अस्यों को भेजी।

(घ) उपर्युक्त (क), (ख) तथा (ग) मदों में रुद्धवित्त मामलों के  
द्वारा में प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की जांच करना  
तथा उसकी प्रभावना एवं जीविकता के निष्कर्षण करना।

(इ) उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) मदों में मन्वर्धित कार्यवाही के विभिन्न मन्दर्भ में सम्पूर्ण मामले में कार्यवाही पर अपर्याप्तता या कमियों (लैप्स) के मुद्दे बनाना।

(ज) इस बारे में भविष्य में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की सिफारिश करना।

(छ) अन्य सम्बन्धित मामलों पर अन्य कोई सिफारिश देना जिन्हें कि समिति आवश्यक या उपयुक्त समझती हो।

4. समिति में अपनी रिपोर्ट तीन माह की अवधि में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

आर एन परदीप, संयुक्त सचिव।

#### MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 24th July, 1985

#### RESOLUTION

Subject: Appointment of a Committee to enquire into the closure of Delhi Cloth Mills and re-development of its complex.

No. H-11016/32/85-DD-II(A) :—The Government have decided to constitute an Official Committee with the following members : —

#### 1. MEMBERS

1. Shri R.L. Pardeep,  
Joint Secretary,  
Ministry of Works & Housing,  
New Delhi.

-- Convenor

2. Shri Virendra Prakash,  
Chief Secretary, Delhi  
Administration, Delhi.

Member

3. Shri Ashok Gupta,  
Joint Secretary,  
Ministry of Labour,  
New Delhi.

Member

4. A representative from the  
Department of Textiles,  
New Delhi.

Member

2. The terms of reference of the committee are: --

(a) to enquire into the circumstances leading to resolution no 26 dated 1st February 1983 of DDA permitting the redevelopment of the DCM complex ;

(b) the circumstances leading to grant of exemption under Section 20(1), read with section 22 of the Urban Land Ceiling Act 1976 by Delhi Admn. vide their Order No. F. 36/10/83-L&B/ULCR dated 14-11-84.

(c) Circumstances leading to and action taken on the notice of closure of Delhi Cloth Mills conveyed vide their letter No. 28833 dated 27-3-85 to Labour Commissioner and others.

(d) to examine and recommend the adequacy and propriety of the action taken by the authorities involved in regard to the matters referred to in items (a), (b) and (c) above;

(e) to indicate points of inadequacy or lapses in action in the entire matter with specific reference to the action referred to in items (a), (b) and (c) above;

(f) to recommend future course of action in this regard;

(g) to make any other recommendations on connected matters which the committee may consider necessary or expedient to make.

3. The Committee will give its report within a period of three months.

R.L. PARDEEP, Jr. Secy.